



## कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय

राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े प्रखण्डों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्राओं को आवासीय प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से राज्य के 187 प्रखण्डों में कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है।

योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

- महिला साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले प्रखण्डों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना,
- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान करना,

योजना उन प्रखण्डों में लागू की गई हैं जहाँ :-

- महिला साक्षरता दर 2001 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय औसत से कम है,
- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी अधिक है,
- छात्राओं का लीजन दर, विशेष रूप से कक्षा 6-8 में अधिक है,

इस विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक आवासीय शिक्षा की सुविधा दी जाती है। यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार के 65-35 प्रतिशत व्यय भार पर संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में योजना के लिए 1250.00 लाख (बारह करोड़ पचास लाख ) रुपये स्वीकृत किए गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2007-09 में 9 अतिरिक्त प्रखण्डों में विद्यालय स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा इस योजना हेतु राज्यांश के रूप में गैर जनजातीय क्षेत्र के लिए 1092.00 लाख (दस करोड़ बानवे लाख ), विशेष अंगीभूत योजना के लिए 336.00 लाख (तीन करोड़ छत्तीस लाख ) एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए 672.00 लाख (छः करोड़ बहत्तर लाख )कुल 2100.00 लाख (इक्कीस करोड़) रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।